अपनी बात

पचपनवें तिब्बती जनक्रांति दिवस का पैगाम

तिब्बती जनक्रांति दिवस अर्थात् 10 मार्च को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार के आयोजन किए गए। वर्ष 2014 में 55वॉ तिब्बती जनक्रांति दिवस था। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में तिब्बत समर्थक संगठनों एवं लोगों ने चीन सरकार द्वारा तिब्बतियों पर किए जा रहे अत्याचार की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए तिब्बत समस्या के समाधान हेतु अपने संघर्ष को ज्यादा प्रभावी बनाने का संकल्प लिया। तिब्बत में जारी अत्याचार के कारण ही गत दो वर्षों में 129 तिब्बतियों ने आत्मदाह कर चुके है। अपने ही हाथों अपने ही पूरे शरीर में आग लगाकर जलते–तड़पते शहीद हो चुके है।

चीन सरकार के अमानवीय व्यवहार से तंग आकर तथा विरोध करने के सारे उपाय बेकार हो जाने पर तिब्बती आत्मदाह कर रहे हैं। तिब्बती आंदोलनकारी चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन सरकार की अमानवीय साम्राज्यवादी नीति को समाप्त करने के ठोस प्रयास किए जायें। तिब्बती जनक्रांति दिवस को भी यह मांग प्रमुखता से सामने आई।

तिब्बत के अंदर और अन्य देशों में भी पीड़ित तिब्बती आंदोलनकारी आत्मदाह करने लगे हैं। ऐसी घटनायें विचलित करने वाली हैं। परम पावन दलाई लामा जी तथा तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री (सिक्योंग) डॉ. लोबसंग संग्ये बहुत ही दुखी हृदय से लगातार अपील कर रहे हैं कि तिब्बती आंदोलनकारी आत्मदाह नहीं करें। उनके अनुसार भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलनेवाले तिब्बती आंदोलनकारी शांति–अहिंसा के मुल्यों से जुड़े रहें। बौद्ध दर्शन में अपने प्रति की गई हिंसा भी गलत है। लेकिन इन करूणापूर्ण अपीलों के बावजूद आंदोलनकारी तिब्बतियों द्वारा आत्मदाह उनकी बेचैनी तथा तिब्बत की बदहाली का ही प्रमाण है।

भारत क्यूंकि तिब्बत का पड़ोसी है, इसलिए तिब्बत समस्या के समाधान में भारत को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। परमपावन दलाई लामा जी भारत को तिबबत का गुरू मानते हैं, क्योकि बौद्ध दर्शन भारत से ही तिब्बत पहुंचा था। इस प्रकार तिब्बती मामले में पड़ोसी के साथ ही भारत को गुरू की भी भूमिका निभानी है। अभी भारत में सोलहवीं लोकसभा के लिए आमचुनाव होने हैं। इस समय तिब्बत के प्रश्न को जोरदार तरीके से उठाना होगा। तिब्बत में मानवाधिकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की चीन सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक उपेक्षा की जा रही है। ऐसे में भारतीय राजनेताओं और राजनीतिक दलों को तिब्बत के पक्ष में और भी निर्णायक तरीके से सामने आना होगा। तिब्बती जनक्रांति दिवस के अवसर पर इस तथ्य को बार–बार रेखांकित किया गया।

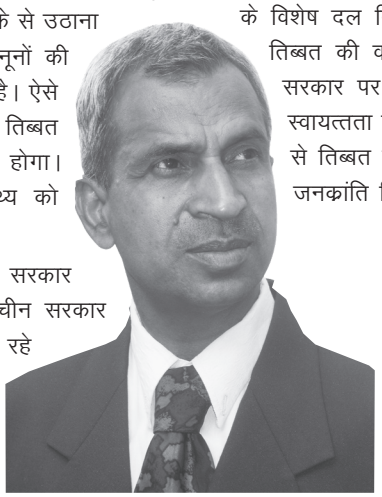

कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थायें तिब्बत के पक्ष में चीन सरकार पर अपने दबाव बढ़ा रही हैं। उनकी नज़र में चीन सरकार बेनकाब हो चुकी है। तिब्बत में उसके द्वारा किए जा रहे तथाकथित विकास एवं संपन्नता की कलई खुल चुकी है। विकास और संपन्नता के नाम पर चीन सरकार तिब्बत में तिब्बतियों को ही साजिशपूर्वक अल्पसंख्यक बना रही है। चीनी मूल के लोगों की संख्या काफी बढ़ा दी गई है और तिब्बती जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एवं पदों पर उनका ही वर्चस्व कायम हो चुका है। यह तिब्बतियों की दोहरी गुलामी है। चीन सरकार के बाद चीन के लोगों की भी गुलामी अपने घर में ही गुलाम बने रहना अत्यन्त अलोकतांत्रिक, कष्टप्रद तथा पाशविक स्थिति है। चीन सरकार के चंगुल से तिब्बत को मुफत कराकर ही इस स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। यह है तिब्बत की पूर्ण आजादी का मार्ग। तिब्बत समर्थक संगठन तिब्बत की पूर्ण आजादी के पक्ष में ही हैं।

अन्य मार्ग है तिब्बत की वास्तविक स्वयत्तता का। परमपावन दलाई लामा जी तथा तिब्बत की निर्वासित सरकार के शब्दों में यह मध्यम मार्ग है। चीन सरकार की संप्रभुता का आदर करते हुए चीनी संविधान एवं कानून के अनुरूप तिब्बत की वास्तविक स्वायत्तता। इससे तिब्बत में धर्म, संस्कृति, प्राकृतिक संसाधन, भाषा, पर्यावरण, दर्शन तथा लोकतांत्रिक मुल्यों की सुरक्षा हो सकेगी। तिब्बती जनक्रांति दिवस को तिब्बत की वास्तविक स्वायत्तता की मांग फिर से की गई। चीन सरकार को चाहिए कि वह इस मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। इस मांग को मान लेने से चीन की अपनी छवि में काफी सुधार होगा। इससे विश्वशांति, विशेषकर एशिया में शांति का वातावरण मजबूत होगा। तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता देकर चीन सरकार अपने ही संविधान एवं कानून का सम्मान करेगी।

इस समय तिब्बत समर्थक संगठन स्वयं को पहले की अपेक्षा ज्यादा मुख्यवस्थित, सशक्त एवं प्रभावी बनाने में लगे हैं। आपसी तालमेल बढ़ाकर तथा एकजुट होकर संघर्ष करने की नीति ने उनमें नई जान डाल दी है। आए दिन समाचार माध्यमों में इस विषय की व्यापक चर्चा हो रही है। तिब्बत को स्वतंत्रता या स्वायत्तता। यह प्रश्न मीडिया में प्रमुखता से छाने लगा है। तिब्बती जनक्रांति दिवस के समारोहों में मीडियाकर्मियों की भारी उपस्थिति ने साबित कर दिया है कि चीन सरकार द्वारा तिब्बत के संबंध में मनगढ़ंत अफवाहों से सबका विश्वास उठ चुका है। स्वतंत्र निष्पक्ष एवं निर्भीक समाचार माध्यमों के प्रतिनिधिमंडल तथा ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेष दल तिब्बत में भेजने की मांग उठने लगी है। इनकी रिपोर्टें तिब्बत की वास्तविक स्थिति से परिचित करायेंगी। परिणामतः चीन सरकार पर चौतरफा दबाव बढ़ेगा और तब तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता जरूर मिलेगी अन्यथा वास्तविक स्वायत्तता मिलने में देरी से तिब्बत की पूर्ण आजादी की मांग मजबूत होगी पचपनवें तिब्बत जनक्रांति दिवस का एक संदेश यह भी है।

प्रो0 श्यामनाथ मिश्रा
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खेतड़ी (राज.)
ek-&9829806065] 8764060406
E-mail & Facebook :- shyamnathji@gmail.com

तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की धर्मशाला में आयोजित वर्षगांठ में यूरोपीय संघ के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए

(तिब्बत डॉट नेट मार्च 14, 2014)

यूरोपीय आर्थिक एवं सामाजिक समिति के अध्यक्ष श्री हेनरी मलोसे 10 मार्च, 2014 को धर्मशाला में तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की 55वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए।

निर्वासित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के केंद्र धर्मशाला में आयोजित तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की 55वीं वर्षगांठ के अवसर पर यूरोपीय संघ के यूरोपीय आा. र्थिक एवं सामाजिक समिति (ईईएससी) के अध्यक्ष श्री हेनरी मलोसे के नेतृत्व में आया एक प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ।

श्री मलोसे ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मध्यम मार्ग नीति का समर्थन करने के लिए ईईएससी प्रतिबद्ध है और इसके लिए भी सहयोग करेगा कि तिब्बत मसले को हल करने के लिए चीन सरकार एवं तिब्बती नेतृत्व के बीच संवाद कायम हो सके। श्री हेन. री मलोसे ने कहा कि यूरोपीय आर्थिक एवं सामाजिक समिति का प्रतिनिधिमंडल तिब्बत आंदोलन को समर्थन देने धर्मशाला आया है जो कि तिब्बत और तिब्बती जनता की आज़ादी, गरिमा और स्वाधीनता एक सार्वभौमिक मसला समझता है। तिब्बत देश को लंबे समय से गरिमा एवं स्वाधीनता से वंचित रखा गया है। इसलिए मैं यहां आया हूं ताकि तिब्बती जनता और चीनी जनता सहित चीन सरकार द्वारा दमित किए जा रहे अन्य सभी लोगों के प्रति एकजुटता दिखा सकूं। उन्होंने यह दोहराया कि मध्यम मार्ग नीति का वह एक प्रगतिशील और यथार्थवादी रास्ते के रूप में समर्थन करते हैं और तिब्बती लोगों द्वारा प्रस्तावित यह नीति स्वाधीनता के सिद्धांतों पर आधारित है, चीन सरकार के साथ संवाद के माध्यम से वास्तविक स्वायत्तता हासिल करने की इच्छा के साथ। उन्होंने कहा कि मध्यम मार्ग नीति से तिब्बती और चीनी, दोनों जनता का भला होगा। ईईएससी के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी प्राथमिकता तिब्बती जनता की पहचान और संस्कृति को बचाए रखना है जिसे चीन सरकार की दमनकारी नीति के तहत खतरा है। श्री मलोसे ने एक मॉडल संगठन के रूप में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा किए गए लोकतांत्रिक सुधारों और तिब्बती शरणार्थियों के बीच उसके प्रभावी कल्याण एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों की तारीफ की।

बाद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री मलोसे ने यूरोपीय संघ में चीनी राजदूत से अपनी हाल की मुलाकाता का जिक्र किया जिन्होंने उनसे धर्मशाला के दौरे की खबर के संदर्भ में कहा था कि वे चीन के आंतरिक मामलों में दखल न दें। उन्होंने चीनी राजदूत से साफ कह दिया था कि तिब्बत एक वैश्विक चिंता है और तिब्बत में मानवाधिकार विषय ईयू–चीन सामरिक वार्ता का हिस्सा हैं। इसके बाद चीन सरक. ार ने तिब्बत के हालात का जायजा लेने के लिए श्री मलोसे को आमंत्रित किया और मलोसे ने उम्मीद जताई की वह जल्दी ही इस दौरे पर जाएंगे। मलोसे ने कहा कि ईईएससी तिब्बत के लिए यूरोपीय संघ का विशेष समन्वयक बनने का प्रयास करेगा।

इस अवसर पर सिक्योंग डॉ. लोबसांग सांगे ने कहा, "आप सब धर्मशाला आए और तिब्बती जनता के प्रति एकजुटता दिखाई, इसके लिए हम गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यूरोपीय आर्थिक एवं सामाजिक समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी स्थिति और तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की 55वीं वर्षगांठ में हिस्सा लेकर आपने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह कड़ा संदेश दिया है कि स्वाधीनता सार्वभौमिक है और इससे तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों को भी उम्मीद का एक मजबूत संदेश मिला है कि दुनिया भर में हमारे मित्र हैं जो हमें सुनते हैं और हमारा समर्थन करते हैं।"

सिक्योंग ने कहा, "चीन सरकार के दबाव के बावजूद आपने खुद यहां आकर तिब्बत और तिब्बती जनता का समर्थन किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हम इस बात की भी सराहना करते हैं कि आप दो खास वजहों से धर्मशाला आए। पहला, मध्यम मार्ग नीति को एक यथार्थवादी रास्ते के रूप में आगे बढ़ाने के लिए ताकि चीन सरकार इसे अपनाते हुए वार्ता के द्वारा तिब्बत मसले को हल करे। दूसरा, आपने यह स्वीकार किया कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन एक सफल संगठन है जो तिब्बती शरणार्थियों की देखभाल कर रहा है जो कि दुनिया के अन्य हिस्सों में हाशिये पर खड़े दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण बन सकता है। हम यह गर्व से कह सकते हैं कि सीटीए पिछले पचास साल से भी ज्यादा समय से काफी प्रभावी तरीके से काम कर रहा है और यह न केवल तिब्बती शरणार्थियों के कल्याण में बल्कि हमारी संस्कृति, पहचान को जिंदा और जीवंत रखने में भी सफल रहा है।"

सीटीए के सूचना एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध के कालोन डिकी छोयांग ने कहा, "हम यूरोपीय आर्थिक एवं सामाजिक समिति के अध्यक्ष के रूप में उनका धर्मशाला में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। यह तिब्बती जनता के लिए काफी महत्व रखता है कि आप अपने सहकर्मियों के साथ इतनी दूर चलकर तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति की 55वीं वर्षगांठ पर तिब्बती जनता की दशा के प्रति एकजुटता दिखाने आए। ◆

भारतीयों ने तिब्बत आंदोलन को लगातार समर्थन देते रहने का वचन दिया

(तिब्बत डॉट नेट, 12 मार्च)

तिब्बत समर्थक समूहों के नेता और आदरणीय आचार्य येशी फुंत्सोक रविवार 9 मार्च, 2014 को आयोजित एक कार्यक्रम में।

उत्तर प्रदेश के तिब्बत समर्थक संगठन भारत–तिब्बत मैत्री समाज ने 10 मार्च को तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की 55वीं वर्षगांठ पर भारत–चीन संबंधों में तिब्बत की सामरिक भूमिका पर एक से. मिनार का आयोजन किया। सेमिनार को संबोधित करते हुए निर्वाचित तिब्बती संसद के सदस्य आचार्य येशी फुंत्सोक ने भारत और तिब्बत के बीच हजारों साल पुराने धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई रिश्ते पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि तिब्बत की सीमा भारत से सटी हुई है चीन द्वारा तिब्बत के पर्यावरण के दोहन और तिब्बती नदियों पर बांध बनाने का निचली जलधाराओं के किनारे स्थित भारत जैसे देशों पर सीधा असर पड़ता है।

सेमिनार में गांधी शांति फाउंडेशन के श्री सुरेंद्र कुमार ने कहा, "1959 में तिब्बत पर चीन के कब्जे से भारत की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ा है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर और लद्दाख की भारतीय सीमा में बार–बार चीनी सेना का अतिक्रमण का खतरा तिब्बत के चीनी उपनिवेश बन जाने की वजह से ही हो रहा है।"

महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सुश्री नीलम चारभा ने कहा कि चीन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार खतरा पैदा करने को देखते हुए भारत सरकार को अपनी विदेशी नीति के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय लोग तिब्बत को एक पवित्र स्थान मानते हैं जहां भगवान शिव का निवास कैलाश मानसरोवर है।

तिब्बत के लंबे समय से समर्थक रहे श्री रमेश भाई और चित्रकूट विकलांग विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. के.बी. पांडे ने कहा कि तिब्बत मसले को हल करने के लिए तिब्बती जनता ने परमपावन दलाई लामा के आध्यात्मिक मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमेशा से ही अहिंसा के सिद्धांत का पालन किया है। उन्होंने कहा, "हम भारत के लोगों को परमपावन के समूची मानवता के प्रति योगदान और समर्पण के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। परमपावन खुद को भारत का बेटा बताते हैं। तिब्बत मसले को हल करने के लिए मध्यम मार्ग नीति अपनाने का भारत को भी समर्थन करना चाहिए। भारत–तिब्बत समन्वय केंद्र (आईटीसीओ) नई दिल्ली ने इस अवसर पर सेमिनार में हिस्सा लेने आए लोगों में तिब्बत संबंधित पुस्तकों का वितरण किया। ◆

अदालत के सार्वभौमिक न्याय के अधिकार को खत्म करने के लिए स्पेन ने किया कानून में बदलाव

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 14 मार्च)

चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन और पूर्व प्रधानमंत्री ली पेंग। फाइल फोटो

फरवरी 2014 में निचले सदन में किए गए बदलावों की तरह ही स्पेन सरकार ने उच्च सदन में भी यह प्रस्ताव पारित कर दिया है कि सार्वभौमिक न्यायिक क्षेत्र के न्यायपालिका के अधिकार में कटौती की जाए। अभी तक स्पेन की अदालतों को यह अधिकार था कि दुनिया में कहीं भी यदि मानवता के खिलाफ अपराध हुआ हो तो वे उसकी सुनवाई कर सकती थीं। लेकिन 12 मार्च को स्पेन की सीनेट ने सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पापुलर पार्टी की वोटिंग के सह. ारे ही प्रस्ताव पारित कर इस कानून में बदलाव कर दिया। इसका तत्काल प्रभ. ाव यह होगा कि चीन के शीर्ष रिटायर्ड राजनीतिज्ञों के खिलाफ अधिकृत तिब्बत में नरसंहार के लिए चल रहे दो मुकदमे खत्म हो जाएंगे। हालांकि, देश की संवैधानिक अदालत से इसे निरस्त करने की अपील की गई है। इस संशोधन का मतलब यह है कि राष्ट्रीय कोर्ट को जो पहले मानवता के खिलाफ अपराध में (चाहे वे दुनिया में कहीं भी हुए हों) सार्वभौमिक न्यायिक क्षेत्र का अधिकार था, वह अब नहीं रहेगा।

संशोधन का मतलब यह है कि अब से स्पेन के बाहर हुए अपराध के लिए स्पेन की अदालत में मुकदमा तब ही चल सकेगा जब इस अपराध का षडयंत्र रचने वाले स्पेन के नागरिक हों या ऐसे विदेशी नागरिक हों जिन्होंने अपराध करने के बाद स्पेन की नागरिकता हासिल कर ली हो। इसका मतलब यह है कि चीन के पूर्व राष्ट्रपति और पार्टी के महासचिव जियांग जेमिन, उनके बाद इस पद पर आए हू जिनताओ और पूर्व प्रधानमंत्री ली पेंग जैसे कई चीनी नेताओं के तिब्बत में नरसंहार के अपराध के लिए स्पेन की नेशनल को. र्ट द्वारा जांच नहीं की जा सकेगी और मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा।

सीनेट में 12 मार्च को बहस के दौरान विपक्ष ने सत्तारूढ़ दल को इस बात के लिए आड़े हाथों लिया कि वह न्यायिक मामलों में 'दखल' दे रहा है। विपक्ष ने कहा कि इससे लोगों के दंड से बच निकलने का रास्ता मिलेगा। पीपी के प्रवक्ता अलफांसो अलोनसो ने कहा कि सार्वभौमिक न्यायिक क्षेत्र को खत्म करना जरूरी था क्योंकि इससे केवल 'टकराव ही पैदा होता है।'

स्पेन की अदालत ने सबसे पहले 1998 में सार्वभौमिक न्यायिक क्षेत्र का इस्तेमाल किया था, जब नेशनल कोर्ट के जज बालतासार गार्जन ने चिली के तानाशाह अगस्टो पिनोशे पर अभियोग चलाया था। बाद में इंटरपोल के द्वारा जारी वारंट के आधार पर लंदन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 17 महीने तक कैद रखा। बाद में इस वयोवृद्ध नेता को स्वास्थ्य कारणों से रिहा कर दिया गया।

विपक्षी समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वह इस संशोधन के खिलाफ देश की संवैधानिक अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। यदि यह संशोधन बरकरार रहता है तो इससे स्पेन की न्यायपालिका में चल रहे दर्जनों मामले खत्म हो जाएंगे। सार्वभौमिक न्यायिक क्षेत्र के पीछे सोच यह थी कि कोई देश ऐसे लोगों के खिलाफ भी अभियोग चला सकता है जो वहां का नागरिक नहीं है, लेकिन जिसने कोई गंभीर अपराध किया हो जैसे मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध, नरसंहार और प्रताड़ना। स्पेन ने इस संहिता को वर्ष 1985 में ही अपने राष्ट्रीय विधेयक में शामिल किया था, लेकिन बाद में वर्ष 2009 में कई देशों के राजनयिक दबाव में इसे थोड़ा हल्का कर दिया गया, खासकर चीन सरकार के दबाव में जिसके नेताओं के खिलाफ ऐसे अपराधों के लिए अभियोग चल रहे हैं। ◆

पूज्यनीय तिब्बती भिक्षुओं को प्रताड़ना की दशा में रख रहा है चीन

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 13 मार्च)

खेनपो कार्तसे

भारी उपेक्षा और कैद में सही उपचार न होने की वजह से तिब्बती बौद्धों की एक अत्यंत पूज्यनीय हस्ती कार्तसे का स्वास्थ्य गंभीर रूप से बिगड़ गया है। रेडियो फ्री एशिया की तिब्बती सेवा द्वारा 11 मार्च की रिपोर्ट में उनके वकील तांग तियान हो के हवाले से बताया गया है कि उनकी हालत बेहद खराब है। उनकी रिहाई की मांग को लेकर उनके गृह नगर क्विंघई प्रांत के युलशुल प्रशासनिक क्षेत्र के नांगछेन काउंटी में कई बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं और अब इन प्रदर्शनों के उग्र हो जाने का खतरा बना हुआ है। कार्तसे को तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र की चामदो काउंटी की पुलिस ने पिछले साल 6 दिसंबर को तब गिरफ्तार कर लिया था जब वह सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू के अपने जापा मठ के लिए धार्मिक वस्तुओं की खरीद कर रहे थे। इसके बाद से ही वह चामदो में कैद में हैं। खबरों के अनुसार उनको "काफी ठंडे कमरे" में रखा गया था जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती और उन्हें पेट भर खाना भी नहीं दिया जा रहा था. यह भी कहा गया कि स्वास्थ्य खराब रहने की वजह से पहले कार्तसे नियमित रूप से अपना मेडिकल चेकअप कराते थे, लेकिन हिरासत में जाने के बाद से उनका उपचार नहीं कराया जा रहा है। रिपोर्ट में मामले से जुड़े एक करीबी सूत्र के हवाले से बताया गया है कि मठ अध्यक्ष के लीवर और फेफड़ों में समस्या है जिसकी वजह से उनके खून के साथ खांसी आती है। उनकी पीठ और छाती में भी दर्द रहता है।

गत 26 फरवरी को अपने मुवक्किल से पहली बार मिलने के बाद तांग तियान हाओ ने संबंधित प्रशासन से यह अनुरोध किया कि कैद में रखे गए भिक्षु का नियमित रूप से चिकित्सीय परीक्षण कराया जाए, जैसा कि "कानूनी प्रावधान है।" उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि उन्हें नहाने की इजाजत देनी चाहिए और ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां सूरज की रोशनी आती हो। लेकिन पुलिस ने उनसे कहा कि वे अपना यह अनुरोध "मामले को देख रहे अधिकारियों" से करें।

चामदो पुलिस ने उन्हें इस आरोप में हिरासत में लिया था कि वह चामदो के कर्मा मठ में "देश विरोधी" गतिविधियों में शामिल रहे हैं। यह बात साफ है कि जब तक वह इन तरह के मामले में शामिल होने की झूठी हामी नहीं भर लेते उनकी कैद के हालात में कोई सुधार नहीं होगा।

खेनपो कार्तसे तिब्बती भाषा, संस्कृति और धर्म को बढ़ावा देने तथा अपने सामा. जिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने वर्ष 2010 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद युलशुल इलाके में राहत कार्यों का भी नेतृत्व किया था। ◆

यूरोपीय समिति के अध्यक्ष दलाई लामा से मिले

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 13 मार्च)

दलाई लामा ने 12 मार्च को धर्मशाला, भारत स्थित अपने आवास पर यूरोपीय आर्थिक एवं सामाजिक समिति (ईईएससी) के अध्यक्ष श्री हेनरी मलोसी का स्वागत किया। मलोसी के साथ ईईएससी का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया था। इसके पहले मलोसी 10 मार्च को तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की 55वीं वर्षगांठ पर निर्वासित तिब्बती प्रशासन द्वारा आयोजित एक समारोह के विशेष अतिथि थे। निर्वासित तिब्बती प्रशासन की वेबसाइट तिब्बत डॉट नेट पर प्रकाशित खबर के अनुसार इस मुलाकात के दौरान दलाई लामा ने श्री मोलासी से कहा कि तिब्बत यदि चीन का हिस्सा बना रहा तो उसकी अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास होगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वास्तविक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि तिब्बत में शिक्षा, पर्यावरण और धार्मिक मामले पूरी तरह से तिब्बतियों के हाथ में हों। दूसरी तरफ, अर्थव्यवस्था और प्रतिरक्षा से जुड़े मामले चीन की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। खबर के अनुसार दलाई लामा ने राष्ट्रपति मलोसी से कहा कि वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आगामी ब्रसेल्स दौरे के दौरान उन तक उनका शांति का संदेश पहुंचाएं और तिब्बत के मसले का हल निकालने का आह्वान करें।

श्री मलोसी ने दलाई लामा को अपना पक्ष साफ तौर से बताते हुए कहा कि यूरोपीय संघ को मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे बुनियादी मूल्यों पर समझौता नहीं करना चाहिए।

श्री मलोसी के साथ इस प्रतिनिधिमंडल में मादी शर्मा (नियोक्ता समूह), तोमास्ज जैसिंकी (कर्मचारी समूह) और एन्ने मारी सिगमंड (विभिन्न हित समूह) शामिल थे। वाशिंगटन आधारित इंटरनेशनल कैम्पेन फॉर तिब्बत के ब्रसेल्स ऑफिस के प्रतिनिधि श्री विनसेंट मेटेन भी इस प्रतिनिधिमंडल के साथ थे। ◆

दो तिब्बती भिक्षुओं ने 2008 की तिब्बती जनक्रांति दिवस की वर्षगांठ पर किया आत्मदाह

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 18 मार्च, 2014)

तिब्बत के क्विंघई प्रांत मे एक व्यक्ति के आत्मदाह के बाद 15 जून को निर्वासित तिब्बती बौद्ध भिक्षु प्रार्थना करते हुए।

वर्ष 2008 में तिब्बती पठार में फैली जनक्रां. ति की छठी वर्षगांठ पर और वहां जारी भीषण चीनी दमन के विरोध में दो तिब्बती भिक्षुओं ने गत 16 मार्च को आत्मदाह कर लिया। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ के अनुसार यह घटनाएं सिचुआन और क्विंघई प्रांत में हुई।

कीर्ति मठ के करीब 20 वर्ष के भिक्षु लोबसांग पालदेन ने सिचुआन प्रांत के नाबा काउंटी की मुख्य सड़क पर सुबह करीब 11.30 बजे खुद को आग लगा लिया। यह घटना 16 मार्च, 2008 की छठी वर्षगांठ पर हुई जब तिब्बत में भिक्षुओं के एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में एक भिक्षु समेत दस लोग मारे गए थे।

खबर के अनुसार लोबसांग पालदेन ने खुद को पेट्रोल में भिगो लिया और इसके बाद आग लगा लिया। इसके बाद वह नारे लगाते हुए कुछ कदम आगे भी बढ़े। चीनी पुलिस तत्काल ही घटनास्थल पर पहुंच गई और आग की लपटों को बुझाकर उन्हें अपने साथ उठा ले गई। तबसे कुछ नहीं पता चल पाया कि वह कहां और कैसे हैं। बताया जाता है कि भिक्षु ने एक लिखित और अपनी आवाज में एक संदेश छोड़ा जिसमें उन्होंने आह्वान किया है कि सभी तिब्बती अपने संघर्ष मे एकता और सच्चाई लाएं। उन्होंने अपनी मां और रिश्तेदारों की दयालुता और लगाव को भी याद किया। बताया जाता है कि घटना के बाद स्थानीय बाजार के तिब्बती दुकानदारों ने अपने शटर गिरा दिए और प्रशासन ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त करते हुए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों और अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की।

शिनहुआ की ही खबर के मुताबिक 16 मार्च को एक और तिब्बती भिक्षु ने क्विंघई प्रांत के जेकोग काउंटी स्थित शादेरी मठ के बाहर आत्मदाह कर लिया। खबर के अनुसार पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई। हालांकि, इस खबर में और विवरण नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ, रेडियो फ्री एशिया की 16 मार्च की खबर में बताया गया है कि आत्मदाह करने वाले भिक्षु सोनाग मठ से जुड़े थे और यह घटना जादोर कस्बे में हुई है। हालांकि, भिक्षु का नाम और विवरण इस खबर में भी नहीं बताया गया है। चीनी अधिकारियों ने सुबह सात बजे हुई इस घटना के बाद इलाके के सभी संचार साधनों पर रोक लगा दी और मठ को चीनी सुरक्षा बलों ने घेर कर इसके अंदर–बाहर लोगों की आवाजाही को रोक दिया।

इसके साथ ही तिब्बत में वर्ष 2009 से अब तक आत्मदाह करने वाले लोगों की संख्या 129 तक पहुंच गई है। ◆

निर्वासित तिब्बतियों पर किस तरह से डरा कर रखता है चीन

(जेफ स्टीन, न्यूजवीक 5 मार्च)

स्वाधीनता आंदोलनकारी ल्हादोन तेथोंग

सभी फोन एक साथ बज रहे थे, वह याद करती हैं: बीप–बीप, ट्रिंग, ब्रिंग! सैन फ्रांसिस्को के एक कमरे में करीब 20 लोग कॉल अटेंड कर रहे थे। अक्सर हेलो? हेलो? की आवाज आती। अक्सर फोन पर अजनबी तरह की आवाजें आती थीं, चीनी लहजे में बोलेने वाले लोग उलटी–सीधी बातें करते थे या पिज़ा का ऑर्डर देते थे। तभी एक फोन से चीखने की भयानक आवाज आई।

प्रमुख तिब्बती स्वाधीनता आंदोल. नकारी ल्हादोन तेथोंग याद करते हुए बताती हैं, "आवाज से ऐसा लगा जैसे कुछ लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा हो।" तत्काल तो उन्होंने यही मान लिया कि यह आवाज फर्जी थी और हो सकता है कि डरावने फिल्म की रिकॉर्डिंग सुनाई गई हो। लेकिन 2008 में उस दिन सैन फ्रांसिस्को में बैठे उम्रदराज लोगों के लिए, जिनको तिब्बत में चीन के बर्बर दमन का व्यक्तिगत अनुभव था यह चीखें इस बात की भयावह याद दिलाने वाली थीं कि भले ही वे कितनी ही दूर क्यों न पहुंच गए हों चीन के लंबे हाथ उनके जीवन तक पहुंच सकते हैं, यहां तक कि अमेरिका में भी।

एफबीआई से रिटायर हो चुके चीन के विशेषज्ञ आई.सी. स्मिथ यहां रहने वाले तिब्बतियों और अन्य विद्रोही समूहों के पीछे लगने के बारे में चीन की हरकत पर कहते हैं, "वे ऐसी कोई भी शरारत कर सकते हैं जो संभव हो।"

लंबा–चौड़ा सुदूर हिमालय की ऊंचाई वाला तिब्बत पठार के गेरुए लबादे वाले बौद्ध भिक्षुओं, 20 फुट लंबे शोक जताने वाले ट्रम्पेट और दलाई लामा का लंबे समय से अमेरिका–चीन के रिश्तों में बड़ी भूमिका रही है। टेक्सास और अलास्का को मिलाकर आकार वाले केंद्रीय एशियाई घास के मैदानों में बिखरे करीब 60 लाख तिब्बतियों की तकदीर पर शायद ही बहुत ध्यान दिया जाता है। फिर भी जैसा कि हाल में फिर यह प्रदर्शित हुआ है, जब राष्ट्रपति ओबामा ने दलाई लामा का व्हाइट हाउस में स्वागत करके बीजिंग को कुपित कर दिया है, एक छोटा सा स्वायत्त चीनी प्रांत, वाशिंगटन के पूर्वी एशियाई गणित का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। दक्षिण चीन सागर में सख्त रवैया दिखाकर ओबामा शायद यह कहना चाह रहे हों, हम आपके पिछवाड़े में आग लगा सकते हैं।

अमेरिका ऐसा पहले भी कर चुका है। कम्युनिस्टों द्वारा वर्ष 1949 में सत्ता हासिल करने के 20 साल बाद सीआईए ने चीन द्वारा बौद्ध प्रांत को हथियाने का विरोध कर रहे तिब्बतियों की मदद की थी, यहां तक कि तिब्बत निर्वासित लड़ाकों को हथियार दिए गए थे और उन्हें कोलोराडो में प्रशिक्षण दिया गया था। वर्ष 1972 में अमेरिका–चीन के रिश्ते सुधारने के प्रयास के तहत तत्कालीन राष्ट्रपति रिचार्ड निक. सन ने सशस्त्र प्रतिरोध को सहयोग बंद कर दिया, लेकिन विदेश मंत्रालय दलाई लामा और उनकी निर्वासित सरकार का सहयोग करता रहा जो 1959 में निर्वासित होकर भारत आ गए थे। चीन अभी भी तिब्बत और भारत मुख्यालय वाले उसके निर्वासित समुदाय को अपने तंत्र में पूरी तरह से समाहित नहीं कर पाया है और दुनिया भर में बिखरा यह तिब्बती निर्वा. सित समुदाय स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहा है।

इस आंदोलन की एक प्रमुख करिश्माई चेहरा हैं 37 वर्षीय तेथोंग जो बोस्टन में रहती हैं और निर्वासित तिब्बती सरकार के एक पूर्व मंत्री की कनाडा में पली–बढ़ी बेटी हैं। तेथोंग स्टुडेंट्स फॉर अ फ्री तिब्बत की पूर्व कार्यकारी निदेशक रही हैं जिसके दुनिया भर में 6,000 स्वयंसेवक और 50,000 अनुयायी हैं। तेथोंग का आ. जकल ज्यादातर समय एक नए प्रोजेक्ट तिब्बत एक्शन इंस्टीट्यूट में बीतता है जो कि आंदोलन पर चीन से होने वाले इंटरनेट हमलों का जवाब देता है और निर्वासित तिब्बतियों को इस बारे में सचेत करता है कि वे संदिग्ध फिशिंग लिंक वाले ई–मेल खोलने से बचें। एक बार यदि हैकर ने ऐसे ई–मेल तक पहुंच बना ली तो वह ई–मेल धारक के कान्टैक्ट, फोन नंबर और ई–मेल पतों तक आसानी से पहुंच सकता है। ◆

परमपावन दलाई लामा और सिक्योंग का अमेरिका के कैपिटल हिल का दौरा

(तिब्बत डॉट नेट, 7 मार्च)

वाशिंगटन डीसी में 6 मार्च, 2014 को कैपिटल हिल पर मुलाकात के दौरान सिक्योंग डॉ. लोबसांग सांगे, सदन की अल्पमत नेता नैंसी पेलोसी (डी–सीए), परमपावन दलाई लामा, सदन के स्पीकर जॉन बोहनर (आर–ओएच) और सदन के बहुमत नेता एरिक कैंटोर (आर–वीए)। फोटोः सोनम जोकसांग

सिक्योंग डॉ. लोबसांग सांगे ने परमपा. वन दलाई लामा के साथ अमेरिकी सदन के नेताओं से मिलने के लिए 6 मार्च, 2014 को वाशिंगटन डीसी स्थित कैपिटल हिल का दौरा किया। उन्होंने अमेरिकी स्पीकर जॉन बोहनर, सदन की नेता नैंसी पेलोसी, बहुमत के नेता एरिक कैंटोर और कांग्रेस सदस्य स्टेनी होयर के साथ करीब 45 मिनट तक बात की। अमेरिकी स्पीकर की वेबसाइट पर उनका बयान दिया गया है, "मुझे परमपावन का अमेरिकी स्टेट कैपिटल में स्वागत कर खुशी हो रही है। धार्मिक आज़ादी और सहिष्णुता के लिए उनकी लड़ाई ने हमेशा से ही दो दलीय कांग्रेस को एक साथ रखा है। इन बातचीत को आगे बढ़ाने और उन्हें समर्थन जताने के लिए आज के लिए उन्हें अपने बीच पाकर मुझे खुशी हुई है।"

इसके बाद अगली सुबह परमपावन ने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के करीब 400 सदस्यों को संबोधित किया। इस दौरान डॉ. लोबसांग सांगे भी मौजूद थे। सीनेटर जॉन मैक्केन तथा कांग्रेस सदस्य नैंसी पेलोसी ने परमपावन तथा सिक्योंग का परिचय कराया। इसमें अमेरिकी प्रशासन के 25 प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

दोपहर में अमेरिकी सीनेट के विदेशी संबंध समिति ने एक वर्किंग कॉफी मी. टिंग का आयोजन किया जिसमें उसके अध्यक्ष सीनेटर रॉबर्ट मेनेनडेज, रैंकिंग सदस्य सीनेटर बॉब कॉर्कर, सीनेटर बेंजामिन कार्डिन, सीनेटर जीन शाहीन, सीनेटर क्रिस्टोफर कूंस, सीनेटर टॉम उडाल, सीनेटर टिम काइनी, सीनेटर मार्को रुबियो, सीनेटर जॉन बरासो भी शामिल थे। इस बैठक में परमपावन ने मानव मूल्यों, धार्मिक सौहार्द को बढ़ाने और तिब्बती संस्कृति, बौद्ध धर्म एवं वहां के पर्यावरण को बढ़ावा देने की अपनी तीन प्रतिबद्धताओं के बारे में बताया। समिति ने तिब्बत के भीतर की मौजूदा स्थिति के प्रति संयुक्त रूप से गहरी चिंता जताई और तिब्बत के मसले पर हर संभव समर्थन देने का वचन दिया। इस दौरान सीनेटर उडाल ने चीनी जनसंख्या के तिब्बत में स्थानांतरण के

वाशिंगटन डीसी में 6 मार्च, 2014 को कैपिटल हिल के अपने दौरे पर परमपावन दलाई लामा अमेरिकी सीनेट के विदेशी संबंध समिति के सदस्यों के साथ। फोटोः जेरेमी रसेल/ओएचएचडीएल

चिंताजनक नतीजों का मसला उठाया और ऐसे कार्यों पर रोक लगाने के लिए हर संभव कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

सिक्योंग डॉ. लोबसांग सांगे ने इस समिति को इस बात की जानकारी दी कि तिब्बत मसले को हल करने के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने किस तरह की मध्यम मार्ग नीति को अपनाया है जो चीनी संविधान के ढांचे के भीतर ही होगा। उन्होंने यह बताया कि तिब्बती प्रशासन न तो अलगाव चाहता है और न ही तिब्बत के भीतर हो रहे मौजूदा दमन को स्वीकार करता है। इसके पहले पांच मार्च, 2014 को नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी ने सिक्योंग के लिए एक रिसेप्शन का आयोजन किया और "निर्वासन में तिब्बती लोकतंत्र की चुनौतियां एवं अवसर" विषय पर वहां उपस्थित करीब 90 लोगों को संबोधित किया।

सिक्योंग अपने निजी सचिव जिग्मे नामग्याल के साथ भारत लौट आए, इसके पहले उन्हें न्यूयॉक के तिब्बत ऑफिस और कैपिटल एरिया तिब्बतन एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरफ से एक विदाई भोज दिया गया। ◆

वाशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल पर 6 मार्च, 2014 को कांग्रेसनल विजिटर्स सेंटर ऑडिटोरियम में आयोजित एक चर्चा के दौरान सिक्योंग डॉ. लोबसांग सांगे, सदन की अल्पमत नेता नैंसी पेलोसी (डी–सीए), सीनेटर जॉन मैक्केन (आर–एजेड), परमपावन दलाई लामा और परमपावन के अनुवादक थुबटेन जिनपा। फोटोः सोनम जोकसांग

तिब्बत का चिरस्थायी अवज्ञा आंदोलन

सेरिंग वूएजर
(न्यूयॉर्क टाइम्स, 2 मार्च, 2014)

सेरिंग वूएजर

गत 27 फरवरी, 2009 को तिब्बती नव वर्ष के तीसरे दिन 24 साल का एक भिक्षु अपने गहरे लाल और पीले रंग के लबादे में दक्षिण–पूर्वी चीन के तिब्बती इलाके में स्थित कीर्ति मठ से गवा की सड़क पर बाहर आया। वहां बने दीर्घायु के देवता के 98 फुट ऊंचे स्मारक की छाया में ही यह व्यक्ति धू–धू कर जल उठा और खत्म हो गया–इस तरह चीन के समूचे तिब्बती इलाके में फैली आत्मदाह की लहर में एक और नाम जुड़ गया। नए साल के समारोह को रोक दिया गया था जिसमें तिब्बती निजी तौर पर उन सभी लोगों को याद कर रहे थे जो कि एक साल पहले कठोर चीनी दमन में पीड़ित हुए थे–उन सभी लोगों को जिनका कत्ल हुआ, जो जेल भेजे गए या गायब हो गए। मार्च 2008 में हुए भीषण दमन में कम से कम चार तिब्बतियों को फांसी देने की सूचना है, हजार से ज्यादा तिब्बतियों को अवैध तरीके से कैद रखा गया और उसके बाद अनगनित अन्य को भी जेल में डाला गया है।

आत्मदाह करने वाले भिक्षु तापे अपने साथ एक नोट छोड़कर गए थे कि यदि वर्ष 2008 के दमन के पीड़ितों को याद करने के लिए आयोजित प्रार्थना समारोह को निरस्त किया गया तो वह खुद को आग लगा लेंगे। जब ऐसे किसी यादगार समारोह को रोकने का आदेश आया तो तापे ने अपनी इस धमकी के अनुरूप ही काम किया।

तापे के मामले से शुरुआत करते हुए मैं अपने ब्लॉग पर हर आत्मदाह की परिस्थितियों बारे में दस्तावेज जुटाने का प्रयास कर रही हूं। मुझे कभी यह अंदाजा नहीं था कि इतने ज्यादा तिब्बती इस रास्ते पर चलेंगे और विरोध प्रदर्शन के नए मॉडल को बढ़ावा मिलेगा। पिछले वर्षों में मैं यह देखकर व्यथित रही हूं कि किस तरह से आग की लपटें एक के बाद एक कर जीवन छीन रही हैं। अभी तक करीब 131 तिब्बतियों ने आत्मदाह के द्वारा अपना जीवन खत्म करने का प्रयास किया है। तापे बचे गए जैसे कि कुछ और लोग भी। लेकिन यह जानना असंभव है कि आत्मदाह की इन घटनाओं में कितने लोगों की जान बच गई है क्योंकि पुलिस उन्हें उठा ले जाती है और इसके बाद उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। इसके पहले कभी भी इतने तिब्बतियों ने चीनी शासन के विरोध में अपना जीवन बलिदान नहीं किया था।

आज तक जारी आत्मदाह की इन घटनाओं से पता चलता है कि हमारी भूमि और जीविका पर 60 साल के चीनी नियंत्रण के बाद भी बीजिंग तिब्बतियों के दिल और दिमाग जीतने से कोसों दूर है और प्रतिरोध को जरा भी कम नहीं किया जा सका है। इसके बावजूद चीन ने हिंसक दमन की अपनी नीति जारी रखी है और उसने सभी के साथ समानता और आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को वापस लाने की तिब्बतियों की मांग को कभी भी स्वीकार नहीं किया है जो कि आधी सदी से ज्यादा समय से निर्वासन में रह रहे हैं। जो लोग तिब्बतियों की दुर्दशा को नहीं

तिब्बत में आत्मदाह करने वाले दो भिक्षुओं को श्रद्धांजलि देने के लिए जलते दीप। फाइल फोटो

समझते वे आत्मदाह को आत्महत्या ही मानते हैं। मरने के जब इतने सारे अन्य तरीके हैं तो कोई भी भला अपने शहरी के एक–एक इंच को जलाकर इस तरह से क्यों मरना चाहेगा? यह सवाल इस तरह की चरम कार्रवाई के पीछे की प्रेरक ताकत को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैः आत्मदाह करने वाले सबसे असाधारण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं खुद को ऐसी पीड़ा देकर जो कि सामान्य व्यक्ति के लिए सहन करना संभव नहीं होता।

एक ऐसा समय था कि जब लगातार तिब्बतियों की एक न एक लहर सड़कों पर आती दिख जाती थी, नारे लगाते हुए और पत्रक बांटते हुए, लेकिन उनकी पिटाई की जाती और उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। इस तरह की जन रैलियों का बस इतना ही असर होता है जैसे कोई पत्थर किसी जलधारा में उछाल दिया गया हो। वर्ष 2008 में बीजिंग द्वारा सख्त दमन शुरू होने के बाद तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र को एक अधिकृत क्षेत्र में बदल दिया गया है, जहां कदम–कदम पर जांच चौकी हैं और हर जगह सैनिक तैनात हैं। अब बड़े प्रदर्शन करना संभव नहीं रहा।

तिब्बती यदि प्रदर्शन करने का मामूली भी अवसर पाते तो वे आत्मदाह का सहारा नहीं लेते। हताशा की इस हालत को लेखक गुद्रुब ने समझा है जिन्होंने स्वायत्तशासी क्षेत्र में आत्मदाह की एक घटना के बारे में अक्टूबर 2012 में लिखा था, "हमारा शांतिपूर्ण संघर्ष अब उग्र हो जाएगा।"

तिब्बत जैसे पुलिस राज्य में आत्मदाह के बारे में जनता की प्रतिक्रिया हासिल करना असंभव है। ज्यादातर तिब्बती सिर झुका के रखते हैं और बीजिंग के अलोकप्रिय आदेशों का भी पालन करने की पूरी कोशिश करते हैं–चीनी राष्ट्रीय झंडा फहराने से लेकर परमपावन दलाई लामा के प्रति अपने सम्मान को छुपाने तक। लेकिन मेरे अनुभवों के मुताबिक ऐसा लगता है कि तिब्बतियों का बड़ा हिस्सा आत्मदाह करने वालों के साथ काफी सहानुभूति रखता है और उन्हें शहीद की तरह देखता है। आत्मदाह करने वालों ज्यादा से ज्यादा लोगों के चित्रों को तिब्बती घरों के पूजास्थलों में जगह मिल रही है।

नवंबर, 2012 में आत्मदाह करने वालों की संख्या बढ़कर शीर्ष 28 तक पहुंच गई थी, जब बीजिंग में 18वीं कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के दौरान नए राष्ट्रीय नेतृत्व का उभार हुआ। इससे साफ था कि आत्मदाह करने वाले यह उम्मीद कर रहे थे कि वे नए नेतृत्व को तिब्बत में नीतिगत बदलाव के लिए प्रेरित कर सकेंगे। लेकिन उनकी उम्मीद पर जल्दी ही तुषारापात हो गया। एक बार पार्टी ने अपना पक्ष चुना तो आत्मदाह के खिलाफ जंग घोषित कर दिया गया और इसमें सहयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की गई। सहयोग करने वालों का मतलब उनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, गांव के लोगों और यहां तक कि आत्मदाह करने वाले के मठ से जुड़े लोगों से था। इसके बाद से सैकड़ों तिब्बतियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में डाला गया है, कई लोगों पर कड़ा जुर्माना लगाया गया है और कई के तो तीर्थयात्रा पर जाने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके बाद आत्मदाह कम हुए हैं, लेकिन यह समझना भूल होगी कि चीन की सख्ती काम आ रही है। बीसवीं सदी के लेखक लु जुन लिखते हैंः "शांति को तूफान आने की आहट समझनी चाहिए।" तिब्बती अभी शांत जरूर दिख रहे हैं, लेकिन उनके आवाज का तूफान किसी दिन तिब्बत और पूरी दुनिया को हिला देगा।

(तिब्बती कवि, पत्रकार और ब्लागर सेरिंग वूएजर "वाइसेज फ्रॉम तिब्बतः सलेक्टेड एस्सेज ऐंड रिपोर्ताज" की सह लेखिका हैं) ◆

तिब्बत और बौद्धों पर चीनियों का बढ़ता शिकंजा

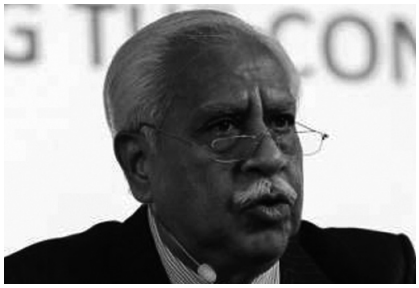

जयदेव रानाडे
(20 मार्च, इंडियन एक्सप्रेस)

चीन की दंगा निरोधी पुलिस तिब्बत की राजधानी ल्हासा के पोटाला महल के सामने गश्त करते हुए।

कई महीनों के अंतराल के बाद इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बीजिंग तिब्बत मसले पर कुछ पहल कर सकता है। इसमें धर्मशाला स्थित दलाई लामा के प्रतिष्ठान से नजदीकी बढ़ाने से लेकर नेपाली एवं भारत के हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले बौद्धों में अपना प्रभाव जमाने और अशांत तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र एवं आसपास के प्रांतों के तिब्बती इलाकों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ मजबूत करना शामिल है. इन खबरों से यह संकेत मिलता है कि चीन और धर्मशाला स्थित तिब्बती प्रशासन के बीच संपर्क सूत्र सक्रिय हो गए हैं। पिछले तीन महीनों में ऐसे कम से कम तीन संपर्क सक्रिय हुए हैं। पहला सीधा संपर्क, दूसरा ताइवान के माध्यम से और तीसरा एक दक्षिण एशियाई देश की राजधानी के माध्यम से जिसे बाद में रोक दिया गया।

शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत मसले को अब प्राथमिकता दे रही है। सबसे रोचक है शी जिनपिंग की मां क्वी शिन द्वारा जिनपिंग के पिता और चीन के पूर्व उप प्रधानमंत्री शी झोंगक्सन की जन्म शताब्दी पर 7,500 शब्दों में लिखा गया एक आलेख। इस आलेख का प्रकाशन तीसरे पार्टी प्लेनम से ठीक पहले 6 नवंबर, 2013 को चाइना यूथ डेली और पीपुल्स डेली में किया गया था। क्वी शिन के आलेख में चालाकी से कई संदर्भ दिए गए हैं जिनसे ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग के परिवार पर बौद्ध धर्म का असर था। तीसरे पार्टी प्लेनम में संयोग से शी जिनपिंग की सत्ता

पर मुहर लगाई गई जिन्हें नवगठित शीर्ष सुरक्षा संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) का भी मुखिया बनना था। बीजिंग में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि एनएससी तिब्बत के मसले पर अभी तक रहे चीन जन राजनीतिक परामर्श सम्मेलन (सीपीपीसीसी) के अधिकार क्षेत्र को हथिया लेगा।

इस मसले पर आंतरिक बौद्धिक बहस भी समझ में आने योग्य है। बीजिंग में रहने वाली प्रख्यात तिब्बती ब्लॉगर वुएजर के हान चीनी पति वांग लिशियोंग ने वाल स्ट्रीट जर्नल के चीनी संस्करण में 4 मार्च 2014 को प्रकाशित लिउ जनिंग के एक आलेख पर टिप्पणी की है। "कनमिंग घटना के आलोक में क्षेत्रीय राष्ट्रीयता स्वायत्तता पर पुनर्विचार" शीर्षक के इस आलेख में चीन के संस्कृत मंत्रालय की सहायक इकाई चीनी संस्कृति संस्थान के रिसर्चर लिउ जनिंग ने आरोप लगाया है कि अल्पसंख्यको के साथ भेदभाव की वजह से चीन की राष्ट्रीयता की समस्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय राष्ट्रीयता स्वायत्तता और राष्ट्रीयताओं के बीच बंटवारे से उनके बीच अलगाव बढ़ा है। इसके पहले पीकिंग विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के चीनी विद्वान मा रोंग ने यह तर्क दिया था कि क्षेत्रीय राष्ट्रीयताओं की स्वायत्तता को खत्म कर देना चाहिए और राष्ट्रीयताओं के बीच विभाजन को भी खत्म करना चाहिए। राष्ट्रीयताओं के बीच शत्रुता और टकराव के लिए इसको मूल वजह बताते हुए वांग लिशियोंग ने यह तर्क दिया कि अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं के लिए विशेष रक्षा उपाय का असम्मान नहीं किया जा सकता। इनमें चारित्रिक अलगाव का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "हान लोगों की विशेषता सबसे पहले मुनाफा देखने की होती है, जबकि तिब्बती, उइगर और मंगोल धार्मिक मान्यताओं और खुशियों की तलाश में रहते हैं। इसलिए उनको एक अरब हान लोगों के साथ बड़े बाजार अर्थव्यवस्था के पात्र में नहीं ठूंसा जा सकता। यह ऐसे ही होगा कि जैसे भिक्षुओं को सैनिकों से लड़ने भेज देना। आव्रजन पर नियंत्रण, पर्यावरण की रक्षा, सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखना और धार्मिक मान्यताओं की रक्षा का सुझाव देते हुए वांग लिशियोंग ने यह बात दुहराई कि क्षेत्रीय राष्ट्रीयता स्वायत्तता की रक्षा के बिना "किसी भी चीनी राष्ट्रीयता को हान की बाढ़ में बहने से रोका नहीं जा सकता क्योंकि हान एक के मुकाबले लाखों की संख्या में होंगे।"

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि क्षेत्रीय राष्ट्रीयता स्वायत्तता को खत्म किया गया तो दलाई लामा द्वारा दशकों से वकालत की जा रही 'मध्यम मार्ग नीति' का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और लोकतांत्रित चीन भविष्य में अधिनायकवादी दमन से राष्ट्रीयताओं के बीच घृणा को खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। यह बताते हुए कि उइगरों का मानना है कि 'दलाई लामा ने तिब्बतियों के 30 साल बर्बाद कर दिये और उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ' उन्होंने कहा कि हाल में उइगर प्रोफेसर इहाम तोहती की गिरफ्तारी से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उनके लिए 'मध्यम मार्ग नीति' सिर्फ कल्पना की चीज है।

साफतौर से बीजिंग के रणनीतिक मंजूरी के बाद नेपाल में तिब्बती बौद्ध संप्रदायों के समारोहों के आयोजनों पर लगे प्रतिबंधों को ढीला किया जा रहा है। शाक्य परंपरा और उनके कई उप संप्रदायों को कई दशकों के बाद लुंबिनी में मोनलम समारोह आयोजित करने की छूट दी गई है। यह एकमात्र तिब्बत बौद्ध संप्रदाय है जिसे अभी इस तरह की इजाजत दी गई है। इस दरियादिली का उद्देश्य यह हो सकता है कि विभिन्न तिब्बती बौद्ध संप्रदायों के बीच मतभेद और गहरे किए जाएं। इससे निश्चित रूप से दलाई लामा की सत्ता कमजोर होगी। नेपाल यह दिखाने की कोशिश करेगा कि जब तक दलाई लामा चीन के सीसीपी नेताओं से मेल–मिलाप नहीं करते उन्हें लुंबिनी के दौरे की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीन नेपाल के मामलों और खासकर बुद्ध के जन्मस्थान लुंबिनी में कितनी रुचि ले रहा है, यह इस बात से साफ दिख जाता है कि चीनी बौद्ध संघ ने लुंबिनी को नए सिरे से विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके पहले नेपाल सरकार लुंबिनी के पुनर्विकास के लिए चीन सरकार प्रायोजित एशिया–प्रशांत विनिमय एवं सहयोग फाउंडेशन (एपीईसीएफ) से 3 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट मंजूर कराने में विफल रहा था। इस प्रोजेक्ट के तहत मठ, होटल और एक एयरपोर्ट बनना है।

एक महत्वपूर्ण घटना से ऊंचे श्रेणी के लामाओं और "पुनर्जन्म" को चयन करने की दिशा में चीन का हाथ और मजबूत हुआ है। चीन ने निनगमा परंपरा के पेनोरे रिनपोछे के पुनर्जन्म की पहचान और उनकी ताजपोशी को मंजूरी दी है। सबसे पहले इस सूचना का खुलासा 5 दिसंबर, 2013 को बयालकुप्पी के नामड्रोल लिंग मठ द्वारा जारी एक बयान से हुआ। निनगमा संप्रदाय तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन संप्रदायों में से है। पेनोर रिनपोछे का पांच साल पहले तिब्बत में निधन हुआ था और इसके बाद जाकर उनके पुनर्जन्म को खोजा गया है। इस पुनर्जन्म की पहचान ल्हासा के नजदीक एक पवित्र जगह पर एक वरिष्ठ लामा द्वारा की गई जो कि 100 वर्षीय जाड्रेल रिनपोछे द्वारा भेजे गए "भविष्यवाणी पत्र" पर आधारित था। नए पुनर्जन्म की औपचारिक रूप से 31 जुलाई को तिब्बत के पालयुल मठ में ताजपोशी की गई। बीजिंग के इस कदम से दलाई लामा, जिनके पास अन्य तिब्बती बौद्ध परंपराओं के प्रमुखों को मंजूरी देने का औपचारिक अधिकार नहीं है, के पास इसके अलावा बहुत कम विकल्प बचा है कि बीजिंग द्वारा मान्य पुनर्जन्म पेनोर रिनपोछे को स्वीकार करें। चीन निश्चित रूप से दलाई लामा के भविष्य से जुड़े मामले में दृष्टांत के तौर पर इस्तेमाल करेगा। ◆

तिब्बत मसले को कैसे हल करें: ओबामा, शी और दलाई लामा को सोचना होगा

सिर्फ ओबामा के दलाई लामा से मुलाकात से तिब्बत की अड़ियल समस्या का समाधान नहीं हो सकता. इसके लिए रचनात्मक समाधान निकालना होगा

केरी ब्राउन
(दि डिप्लोमेट, 4 मार्च)

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा (दाएं) ने 21 फरवरी, 2014 को व्हाइट हाउस के मैप रूम में परमपावन दलाई लामा से मुलाकात की।

गत 21 फरवरी को राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में 14वें दलाई लामा से मुलाकात की। यह उनके अपने प्रशासन के दौरान ओबामा से हुई तीसरी मुलाकात है। यह मुलाकात ओवल ऑफिस में नहीं हुई, लेकिन इस मुलाकात के प्रतीकवाद ने अनुमान के मुताबिक ही ग्रीन को काफी नाराज किया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने आलोचना की अगुवाई करते हुए कहा कि यह मुलाकात दुनिया की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच रिश्ते को 'बिगाड़ने' और 'दुर्बल' करने का काम करेगी।

हालांकि, बाहर के लोग कुछ अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कठोर राजनीतिक पदों में देखें तो यह अब साफ हो गया है कि महाशक्ति अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश बचा है जो इस तरह की मुलाकात का जोखिम लेने का इच्छुक है। वर्ष 2012 के मध्य में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की दलाई लामा से मुलाकात के बाद ब्रिटेन और चीन के रिश्तों पर एक साल तक बर्फ जम गई थी। कैमरन ने सबसे ज्यादा मेलमिलाप का रवैया दिखाया और आखिरकार पिछले साल दिसंबर में उन्हें चीन के दौरे की इजाजत दी गई। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या वह सत्ता में रहने के दौरान दलाई लामा से दोबारा मिलना चाहेंगे, तो कैमरन का सीधा जवाब था, अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि अब वह यह करेंगे। दूसरे अन्य यूरोपीय संघ देशों के मामले में भी

ऐसा ही कहा जा सकता है। वर्षों तक चीन की कड़ी प्रतिक्रिया और राजनयिक पलटवार का फायदा चीन को मिलता दिख रहा है।

अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत है। इसलिए वह और सिर्फ वही दलाई लामा और अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष के बीच ऐसी मुलाकात का आयोजन कर सकता है। घरेलू स्तर पर देखें तो ओबामा की ऐसी मुलाकात का फायदा भी है। अमेरिका में यह मानने वाली एक तगड़ी लॉबी है कि बीजिंग पर ज्यादा दबाव बनाया जाना चाहिए और तिब्बत मसले पर सबसे ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

यहां तक कि, अब जब इस मुलाकात के नाटक और उसके नतीजे की भरपाई हो गई है तो भी कड़वा तथ्य यही है कि आत्मदाह लगातार जारी हैं। पिछले तीन साल में तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में सौ से ज्यादा लोगों ने आत्मदाह किए हैं। इस इलाके में राजनीतिक एवं विकासात्मक चुनौतियां अब भी उतनी ही महत्वपूर्ण तथा अड़ियल बनी हुई हैं, जितनी कि ओबामा–दलाई लामा मुलाकात से पहले थीं। कीव (यूक्रेन) में खूनखराबा देख रही चीन सरकार के लिए इस मसले पर नरमी बरतने का विचार दिन–ब–दिन कम कम आकर्षित कर रहा है।

तिब्बत वास्तव में चीन की समस्या है, उन वजहों से नहीं जो ज्यादातर बाहरी लोग मानते हैं। चीन सरकार ध ार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी को कम प्राथमिकता देती है। उनका मुख्य सिरदर्द यह है कि तिब्बत का अपना विकासात्मक और आर्थिक गणित विफल हो रहा है। तिब्बत अपने लगभग समूचे बजट के लिए केंद्रीय सब्सिडी पर निर्भर करता है। तिब्बत की अर्थव्यवस्था के बारे में विद्वान एमिली ये के एक बेहतरीन अध्ययन से यह पता चलता है कि केंद्र सरकार के धन का भारी हिस्सा वास्तव में वहां आता तो है, लेकिन उसी तरह से बाहर भी चला जाता है क्योंकि वहां बड़ी संख्या में बाहरी लोग हैं, खासकर पड़ोसी सिचुआन प्रांत से आने वाले चीनी लोग जो वहां थोड़े समय के लिए काम करते हैं, धन कमाते हैं और उसे अपने घर भेज देते हैं। अपने प्राकृतिक संसाधनों की वजह से वास्तव में तिब्बत को एक संपन्न प्रांत होना चाहिए था। लेकिन इन संसाधनों का दोहन करना कठिन है और बड़े पैमाने पर किए जाने वाले दोहन की भारी पर्यावरण कीमत चुकानी पड़ी है। संसाधनों की भूखी केंद्रीय सरकार इन संभावित खनिज संपदा के दोहन के लिए नजरें गड़ाए बैठे है, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि चीन के लिए सबसे कीमती संसाधन जल तिब्बती पठार से आता है। गलत तरीके से दोहन से आखिरकार चीन को टिकाऊपन के समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, मौजूदा समय से भी ज्यादा।

चीन सरकार तिब्बत पर बाहरी लोगों के विचार सुनने को इच्छुक नहीं दिखती। ओबामा के साथ दलाई लामा की मुलाकात पर उनकी प्रतिक्रिया पहले जैसी ही रही है। उनके मुताबिक यह एक बेवजह राजनीतिक दखलंदाजी है जिसका उद्देश्य कम्युनिस्ट पार्टी के शासन पर हमला और उसे अस्थिर करना है। इन सबके बाजवूद चीन में इन विच. ारों का भारी अकाल देखा जा सकता है कि तिब्बत में क्या किया जाए, वहां दीर्घकालिक स्थिर सरकार और प्राकृतिक दशाओं के लिहाज से। वर्ष 2008 की तरह ही एक और व्यापक जनक्रांति की भयंकर संभावना बनी हुई है। खासकर यदि दलाई लामा बीमार पड़ते हैं या उनकी मौत हो जाती है। अभी तक तो इस इलाके में पिछले कई दशकों में हुए विरोध प्रदर्शन काफी शांतिपूर्ण रहे हैं। दलाई लामा ने किसी भी तरह के हिंसा के इस्तेमाल की खिलाफत करते रहे हैं। लेकिन भविष्य में ज्यादा कट्टर आवाज इस अपील को नजरअंदाज कर सकता है।

बीजिंग प्रशासन को तिब्बत से निप. टने के लिए कुछ नए विचारों की जरूरत होगी, लेकिन कुछ सबसे कारगर विच. ारों के लिए उन्होंने अपने दिमाग बिल. कुल बंद कर रखे हैं। संघवाद उन्हें नाराज करता है और उनको लगता है इलाके को पूरी स्वायत्तता मिल चुकी है जितने की जरूरत है, इसलिए सत्ता हस्तांतरण की बात उनके गले तो नहीं उतरने वाली है। साफतौर से वे ज्यादा क्रांतिकारी समाधान के जोखिम को उठाने को तैयार नहीं दिखते। उनकी एकमात्र रणनीति यही है कि अपना पूरा जोर आर्थिक विकास पर लगाया जाए और उन्हें उम्मीद है कि इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। उनके इस मामले में ज्यादा आत्मविश्वास की वजह कम ही दिख रही है। लोग यदि ज्यादा भौतिक संपन्नता से ही संतुष्ट हो जाते तो दुनिया भर में शासन चलाना बहुत आसान होता जैसा आज है उसके मुकाबले।

ओबामा और दलाई लामा जैसी इन मुलाकातों का अपना काफी प्रतीकात्मक महत्व है, निर्वासित तिब्बतियों के लिए भी और नकारात्मक ही सही बीजिंग प्रशासन के लिए भी। लेकिन अभी तक मौजूदा चुनौतियों का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। दुनिया को इन मसलों पर चीन के साथ बेहतर स्तर का संवाद करना चाहिए और यह दिखावे एवं राजनीतिक छल–प्रपंच से दूर होना चाहिए। चीन के बाहर एवं भीतर हर किसी को तिब्बती इलाके की स्थिरता के बारे में चिंतित होना चाहिए।

इस समय तो जो चीजें हो रही हैं वे बहुत आश्वस्त करने वाले नहीं हैं। हमें सुझावों और विचारों के आदान–प्रदान के लिए ज्यादा खुला माहौल चाहिए। लेकिन फिलहाल तो तिब्बत पर बहस को लेकर तरीका और रवैया काफी विभाजित और रक्षात्मक है। यह अत्यंत दयनीय बात है क्योंकि इस मसले पर तो लगातार ध्यान देने की जरूरत है। तिब्बत और उसके भविष्य के बारे में सहिष्णुता एवं रचनात्मक बहस की कमी न सिर्फ बीजिंग की समस्या है, बल्कि हम सबकी समस्या भी है। ◆

फालिंग थ्रू द रूफ

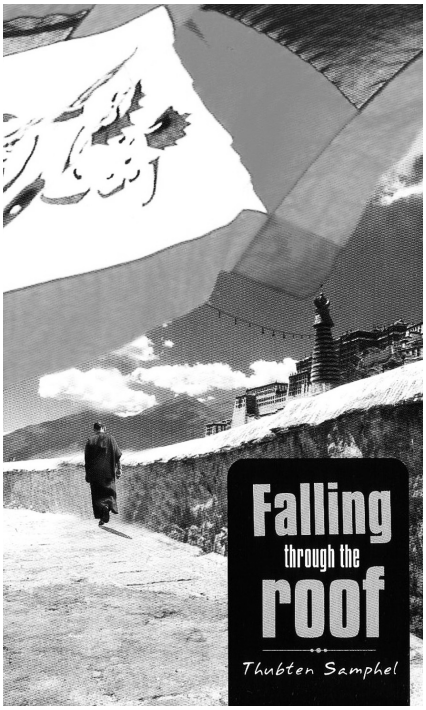

पब्लिशरः रूपा एंड कंपनी
लेखकः थुबटेन सामफेल
पेजः 308
कीमतः 295 रूपए
समीक्षाः त्सेरिंग नामग्याल

प्रयास कर सामान्य और प्रवाहपूर्ण गद्य में लिखी भारत में रहने वाले तिब्बती लेखक थुबतेन सामफेल का पहला उपन्यास 'फालिंग थ्रू द रूफ' टाशी के जीवन से होकर गुजरता है जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र है। अपने आदर्शवादी एवं उत्साही साथियों के साथ टाशी एक दिन तिब्बती कम्युनिस्ट पार्टी के गठन का निर्णय लेता है जिससे उसे लगता है कि उसके अशांत देश को आधुनिक दुनिया में शामिल करने में मदद मिलेगी। वे दिन में खूब पढ़ाई करते हैं, इतिहास, साहित्य पर निबंध लिखते हैं, कार्ल मार्क्स एवं फ्रांत्ज फन्नोन को पढ़ते हैं। शाम को वे कुछ पीने जाते हैं दिल्ली से बाहर एक उभरती तिब्बती बस्ती में, जहां उनके बहुत से तिब्बती देशभाई जौ और चावल से बने बियर (जिसे छंग कहते हैं) बेचकर अपनी जिविका चलाने के लिए परेशान रहते हैं, लहरदार टीन शेड से ढंकी झोपड़ियों में। वे स्वादिष्ट छंग पीते हुए देश–दुनिया की राजनीति की चर्चा करते हैं। इस उपन्यास का काफी घटनाक्रम इस 'छंगिस्तान' में ही दिखता है जहां उपन्यास का नायक टाशी और कथा बताने वाला कुंगा धोनडुप एक उच्च स्तरीय तिब्बती भिक्षु से मिलते हैं इस होशियारी से कि 'तिब्बत की कहानियां' पता चल सकें। छंग पीने की कमजोरी रखने वाले भिक्षु इन छात्रों को तिब्बत के अतीत की कहानियां बताते हैं और अचानक उन्हें लगता है कि टाशी एक बड़े तिब्बती लामा का पुनर्जन्म है जिन्होंने तिब्बती भाषा की खोज की है। कश्मीर में इस भाषा की खोज से ही तिब्बती विद्वान भारत के दर्शन और ज्ञान को हिमालयी पठार तक पहुंचा पाए।

इस तरह यह उपन्यास कश्मीर ले जाता है, उस मूल स्थान की खोज करने के लिए जहां लामा ने भाषा की खोज की थी। सामफल तथ्य (यहां तक कि जवाहर लाल नेहरू, भारत में विपक्ष के नेता और तिब्बत समर्थक राज नरायण, मंगोलियाई शासक कुबलाई खान और मार्को पोलो ने इसकी चर्चा की है) और कल्पना का मिश्रण कर तिब्बती अक्षरों का उद्‌गम तलाशते हैं।

हालांकि, यह कोई इतिहास की किताब नहीं है जिसमें सामफेल भारत में निर्वासन में रहने वाले लोगों की कहानी बताने की धुन में हों। सामफेल की जीवंत और वर्णनात्मक भाषा पूरे उपन्यास में दिखती है और उन्होंने सबसे अच्छे तरीके से वर्णन दिल्ली के दृश्यों, कॉलेज छात्रों के बीच झगड़ों, सड़कों पर उनके विरोध प्रदर्शन करने के जुनून और प्रेम प्रसंगों का किया है। सामफेल के बेहतरीन मनोविनोद की वजह से कई जगहों पर आप हंसते हुए लोटपोट हो सकते हैं।

'फालिंग थ्रू द रूफ' एक महत्वाकांक्षी पुस्तक है अपनी संभावना और दृष्टि, दोनों के लिहाज से। एक अत्यंत मनोरंजक और बंधे रहने लायक कहानी पेश कर लेखक तिब्बतियों की परंपरागत दुनिया और निर्वासन की मिली–जुली दुनिया की अच्छी आंतरिक झलक पेश करता है। एक मातृभूमि न होने की कुंठा से गुजर रहे चरित्रों के पास उम्मीद भी है, अपनी युवा ऊर्जा की बदौलत ही वे अपनी इस विशिष्ट दशा के ऊपर हंस सकने की क्षमता रखते हैं।

सामफेल का जन्म तिब्बत में हुआ था, लेकिन वह भारत में पले–बढ़े हैं। दिल्ली और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े सामफेल फिलहाल निर्वासित तिब्बती सरकार के तिब्बत नीति संस्थान में निदेशक हैं। 'फालिंग थ्रू रूफ' में सामफेल दिखाते हैं कि जब तिब्बतियों ने अपना घर खो दिया तो बदले में पूरी दुनिया उनका घर बन चुकी है। उनकी संस्कृति आज भी फल–फूल रही है, भले ही विभिन्न मिश्रित रूपों में सही। भारत में रचा गया एक बेहतरीन उपन्यास अपने आप में तिब्बतियों के लचीलेपन का प्रमाण है। ◆